अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता जरूरी : गवर्नर

बैंकिंग कॉन्क्लेव में आरबीआई ने रिफॉर्म्स पर जोर दिया

रेगुलेटरी बदलावों से मजबूत हुआ देश का बैंकिंग सिस्टम

मल्होत्रा ने एसबीआई का उदाहरण देते हुए बताया कि 2018 में नुकसान में चला गया देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक आज 100 बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुका है, जो रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल सुधारों का परिणाम है. उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय स्थिरता के बिना शॉर्ट-टर्म ग्रोथ खतरनाक हो सकती है और देश की आर्थिक नींव को कमजोर कर सकती है. मल्होत्रा के अनुसार, आरबीआई का लक्ष्य बैंकिंग सिस्टम को तकनीकी बदलावों के बावजूद स्थिर, निष्पक्ष और मजबूत बनाए रखना है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक स्वस्थ रहे.

मुंबई, 7 नवंबर.भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 12वें बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय स्थिरता बेहद जरूरी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल शॉर्ट-टर्म ग्रोथ हासिल करने का समय नहीं है, बल्कि लंबी अवधि की वृद्धि के लिए मजबूत वित्तीय ढांचा जरूरी है.

मल्होत्रा ने कहा कि हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और टेक्नोलॉजिकल बदलावों के कारण बैंकिंग सिस्टम तेजी से बदल रहा है. ऐसे में रेगुलेटर की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि बैंकिंग क्षेत्र स्थिर, निष्पक्ष और मजबूत नियमों के तहत विकसित हो. उन्होंने पिछले कॉन्क्लेव में किए गए रेगुलेटरी सुधारों का उल्लेख करते हुए बताया कि आरबीआई ने अपने लिए कंसल्टेटिव और ओपन रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनाया है. इसके अलावा, उन्होंने इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी सुधारों को देश के क्रेडिट कल्चर में क्रांति के रूप में बताया. एसबीआई के प्रदर्शन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 2018 में नुकसान में रहे देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक ने रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल सुधारों के कारण आज 100 बिलियन डॉलर की कंपनी बनकर वित्तीय मजबूती साबित की है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को 12वें बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 में वित्तीय स्थिरता की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के हित में यह जरूरी है कि आरबीआई केवल शॉर्ट-टर्म ग्रोथ के लिए जोखिम न उठाए. वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने से ही लंबे समय तक स्थायी आर्थिक वृद्धि संभव है. मल्होत्रा ने बताया कि कॉन्क्लेव ऐसे समय में हो रहा है जब राजनीतिक तनाव और टेक्नोलॉजिकल बदलावों की वजह से अनिश्चितताएं बनी हुई हैं.

उन्होंने पिछले साल हुए कॉन्क्लेव का उल्लेख करते हुए कहा कि तब उन्होंने टैक्सेशन और बैंकिंग सेक्टर में हो रहे सुधारों पर चर्चा की थी. गवर्नर ने बताया कि आरबीआई ने अपने लिए एक कंसल्टेटिव और ओपन रेगुलेशन फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिससे रेगुलेटरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बने. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और तेजी से बदलते बैंकिंग सिस्टम में रेगुलेटर की जिम्मेदारी यह है कि वह स्थिरता, निष्पक्षता और मजबूती के नियमों के तहत विकास को सुनिश्चित करे.

शेयर बाजारों में हल्की गिरावट

नई दिल्ली, 7 नवंबर. देश के शेयर बाजारों में गुरुवार को हल्की गिरावट देखने को मिली. कारोबारी सत्र के दौरान निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स 94.73 अंक या 0.13% की गिरावट के साथ 78,450.25 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 17.40 अंक यानी 0.09% कमजोर होकर 23,734.10 पर आ गया. शुरुआती कारोबार में दोनों सूचकांकों में सीमित बढ़त देखी गई थी, लेकिन दिनभर की मुनाफावसूली ने बाजार को दबाव में ला दिया. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, निवेशक इस समय घरेलू कॉर्पोरेट नतीजों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति को लेकर सतर्क हैं.

Ministry of External Affairs
Government of India

भारत-फिनलैंड ने डिजिटल और हरित तकनीक पर दिया जोर

तकनीकी, व्यापार और शिक्षा में नया आयाम देने का किया संकल्प

लोगों के बीच संबंध के क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूत करने की प्रतिबद्धता

नयी दिल्ली 7 नवम्बर. भारत और फनिलैंड ने व्यापार एवं निवेश, डिजिटलीकरण, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5 जी और 6 जी प्रौद्योगिकी , कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग मज़बूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है. भारत और फिनलैंड के बीच 13 वें विदेश कार्यालय परामर्श की हेलसिंकी में गुरुवार को हुई बैठक में यह सहमति बनी.

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां एक वक्तव्य जारी कर बताया कि फिनलैंड ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अपना समर्थन दोहराते हुए समझौते के जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई है.

बैठक में भारत का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने और फनिलैंड का नेतृत्व फनिलैंड के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव जुक्का सलोवारा ने किया. हेलसिंकी यात्रा के दौरान सचिव (पश्चिम) ने फनिलैंड के रोज़गार मंत्री मतियास मार्टिनेन से भी शिष्टाचार भेंट की.

दोनों पक्षों ने भारत-फनिलैंड द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और व्यापार एवं निवेश, डिजिटली करण, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5 जी/ 6 जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सततता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास और लोगों से लोगों के बीच संबंध के क्षेत्रों में सहयोग को और मज़बूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की. भारत फनिलैंड को यूरोपीय संघ और नॉर्डिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण और विश्वसनीय भागीदार मानता है.

वैश्विक चुनौतियों पर निरंतर संवाद के महत्व को रेखांकित किया

फिनलैंड ने पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपने समर्थन को दोहराया . दोनों पक्षों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया . उन्होंने बहुपक्षीय सहयोग और वैश्विक चुनौतियों पर निरंतर संवाद के महत्व को रेखांकित किया . दोनों देशों के बीच अगली बैठक भारत में होगी .

विद्युत ऊर्जा का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम खुलेगा

मुख्य निवेशकों के लिए बोली 10 नवंबर को शुरू होगी

निर्गम का कुल आकार लगभग 2,900 करोड़ है

मुंबई, 7 नवंबर. देश की अग्रणी सौर खंड और कोष्ठिका निर्माता एमवी प्रकाश-विद्युत ऊर्जा लिमिटेड का बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम 11 नवंबर, 2025 को खुलेगा और 13 नवंबर को बंद होगा.

कंपनी ने 2 अंकित मूल्य वाले अपने समता शेयरों के लिए मूल्य पट्टी 206 से 217 प्रति समता शेयर निर्धारित की है. मुख्य निवेशकों के लिए बोली 10 नवंबर को शुरू होगी. निवेशकों को न्यूनतम 69 समता शेयरों के लिए बोली लगानी होगी.

निर्गम का विवरण और कंपनी की स्थिति- इस प्रस्ताव में 2,143.86 करोड़ का एक नया निर्गम और प्रवर्तकों द्वारा 756.14 करोड़ की बिक्री का प्रस्ताव सम्मिलित है, जिससे निर्गम का कुल आकार लगभग 2,900 करोड़ है.

क्रिसिल प्रतिवेदन के अनुसार, एमवी प्रकाश-विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की दूसरी सबसे बड़ी शुद्ध एकीकृत सौर प्रकाश-विद्युत खंड और कोष्ठिका निर्माण कंपनी है. 30 जून, 2025 तक, कंपनी के पास 7.80 अरब वाट की खंड उत्पादन क्षमता और 2.94 अरब वाट की कोष्ठिका उत्पादन क्षमता है. यह कंपनी उच्च दक्षता वाली टनल ऑक्साइड निष्क्रिय संपर्क तकनीक को अपनाने वाली शुरुआती कंपनियों में से एक है.

सभी बोलीदाताओं को अनिवार्य रूप से अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन प्रक्रिया का उपयोग करना होगा.

यह निर्गम पुस्तिका निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है . निर्गम का आवंटन इस प्रकार होगा-

75 प्रतिशत हिस्सा योग्य संस्थागत क्रेताओं के लिए आरक्षित होगा .

15 प्रतिशत हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा .

10 प्रतिशत हिस्सा खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं के लिए आरक्षित रहेगा .

सोना-चांदी के दामों में गिरावट

नई दिल्ली, 7 नवंबर. कीमती धातुओं के दामों में शुक्रवार को नरमी देखी गई. सोना और चांदी दोनों के भाव अपने-अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुके हैं. घरेलू बाजार में सोने का दाम जीएसटी समेत 1,23,837 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी की कीमत जीएसटी समेत 1,52,450 प्रति किलो है. जानकारी के अनुसार, सोना अपने 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से अब तक 10,643 सस्ता हो गया है. वहीं, चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है—यह 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 30,090 प्रति किलो तक टूट चुकी है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स में मजबूती और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है.

भारत के साथ गहरी साझेदारी की संभावनाएं

गोयल ने भारत-न्यूजीलैंड के बीच प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग पर दिया जोर

रोटोरुआ (न्यूजीलैंड), 7 नवंबर. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड की अपनी आधिकारिक यात्रा के दूसरे दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार, निवेश, संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के उद्देश्य से कई उच्च-स्तरीय बैठकें की हैं.

गोयल ने यहां न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकक्ले के साथ भारत-न्यूजीलैंड सीईओ गोलमेज सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख व्यावसायिक प्रतिनिधि मौजूद थे. उन्होंने भारत के तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य का उल्लेख किया और प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन और स्थिरता में सहयोग की संभावनाओं को रेखांकित किया. उन्होंने भारतीय मूल के व्यापारिक दिग्गजों की मजबूत भागीदारी का स्वागत किया और न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को पारस्परिक विकास के लिए भारत के साथ गहरी साझेदारी की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया. इससे पहले रोटोरुआ जाते समय श्री गोयल ने एयर न्यूजीलैंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल रविशंकर से मुलाकात की. उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक संपर्क बढ़ाने में एयरलाइंस की भूमिका पर चर्चा की.

भारत की सामरिक अवसंरचना को नई दिशा

नई दिल्ली, 7 नवम्बर . रक्षा और सार्वजनिक अवसंरचना विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए, भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को चेन्नई के अवाडी स्थित बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (एवीएनएल) की इकाई हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री (एचवीएफ) से 350 करोड़ रुपये की परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) परियोजना का कार्य सौंपा गया है. यह कार्य गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) प्रक्रिया के तहत प्रदान किया गया है. इसमें प्रमुख पूंजीगत सिविल कार्यों के डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रबंधन शामिल हैं, जो देश की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाएंगे. एनबीसीसी इस परियोजना में एवीएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय परिसर, आयुध विकास केंद्र, ओवरहाल क्षमता बढ़ाने हेतु परीक्षण ट्रैक अवसंरचना, तथा कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण की जिम्मेदारी निभाएगा.

फेस्टिव सीजन में ऑटो रिटेल ने बनाया रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 7 नवंबर. अक्टूबर का महीना भारत में ऑटो मार्केट के लिए बेहद यादगार रहा. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) के ताजा आंकड़े बताते हैं कि जीएसटी रेट कट और फेस्टिव सीजन की बढ़ती मांग के चलते वाहनों की खुदरा बिक्री इस साल अक्टूबर में 40.2 लाख यूनिट तक पहुंच गई.

यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 40.5 प्रतिशत अधिक है, जब बिक्री 28.7 लाख यूनिट थी. विशेष रूप से टू-व्हीलर सेगमेंट ने सबसे अधिक योगदान दिया.

14 निशानेबाजों को मिलेगी नई ताकत

मुंबई, 7 नवंबर. भारतीय सेना की 'मिशन ओलंपिक्स विंग' के तहत आने वाली प्रतिष्ठित आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट महू ने शूटिंग-प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस फाउंडेशन के साथ अपनी पहली कॉर्पोरेट पार्टनरशिप की है.

यह पार्टनरशिप 14 निशानेबाज़ों को सपोर्ट करेगी, जो फिलहाल एएमयू में प्रशिक्षण ले रहे हैं. इनमें पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले संदीप सिंह और सेना की पहली महिला सुबेदार प्रीति रजक शामिल हैं. रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता एम. अंबानी ने इस मौके पर कहा भारतीय सेना और आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट के साथ जुड़ना हमारे लिए सम्मान की बात है. यह साझेदारी केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक संकल्प है, भारत को खेलों में शीर्ष स्थान दिलाने का. हम मिलकर ऐसे चैंपियनों को तैयार करेंगे जो देश का गौरव बढ़ाएँगे. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा जैसे अनेक बेहतरीन खिलाडियों को जन्म दिया है, जिन्होंने कई मौकों पर भारत और भारतीयों का सिर शान से ऊंचा कराया है.

समाचार विशेष

महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा

आरजडी-जडीयू किसके लिए है ये गुड न्यूज?

पटना. बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 64.46 फीसदी वोटिंग हुई है. जो कि पिछली बार से 7.50 प्रतिशत ज्यादा है. वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में 56.9 फीसदी वोटिंग हुई थी. इस बार महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही. जिसकी वजह से कई प्रकार की चर्चा शुरू हो गई है.

सीनियर पत्रकार लव कुमार कहते हैं कि 10 हजार की स्कीम एनडीए की कोर महिला वोटरों में जोश भरने का काम किया है. सरकार ने चुनाव से ठीक पहले डेढ़ करोड़ महिलाओं के हाथ में 10 हजार रुपये दे दिए थे. यह उसी का असर है. हालांकि अभी तक का ट्रेंड रहा है कि बंपर वोटिंग होने पर सरकार बदल जाती है.

बिहार में करीब करीब 40 फीसदी महिला वोटरों है. चुनाव के जानकार विनोद कुमार कहते हैं कि बिहार सरकार ने डेढ़ करोड़ महिला वोटरों को 10 हजार दिए थे. इससे उन्होंने करीब साढ़े चार करोड़ (प्रति परिवार चार सदस्य मानें तो) वोटरों को साध लिया है. अगर सरकार का यह जादू चल गया है तो बिहार में बंपर वोटिंग का यह बड़ा कारण है. जो कि एनडीए के कोर वोट ग्रुप में वोटिंग के लिए जोश भरने जैसा है.

क्या 10 हजार वाली स्कीम काम कर गई?

बिहार मे पहले चरण के चुनाव के बाद एक बार फिर से 10 हजार की स्कीम की बड़ी चर्चा हो रही है. बिहार सरकार ने महिलाओं को 10 हजार रूपया अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया है. यह पैसा वापस नहीं करना है. जो महिला इस पैसा का लाभ लेकर अपना कारोबार बड़ा करती है तो सरकार उन महिलाओं को दो लाख रूपये तक देने का वादा किया है. सरकार का यह स्किम कारगर होता दिख रहा है. हालांकि कुछ दिन पहले हुए एक सर्वे में महिला वोटरों के मामले में नीतीश को तेजस्वी पर 32 पर्सेंट की बढ़त हासिल है.

एमवीए क्या एकजुट होकर लड़ेगा चुनाव?

मुंबई. महाराष्ट्र में वोट गड़बड़ी के सवाल पर महा विकास अघाड़ी यानी एमवीए के घटक दल एकजुट हुए हैं. काफी समय के बाद सभी घटक दलों ने मुंबई एक प्रदर्शन किया और रैली का आयोजन किया. इसमें कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट भी शामिल हुए और शरद पवार भी शामिल हुए.

ध्यान रहे कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति थी कि उद्धव ठाकरे क्यों राज ठाकरे को गठबंधन में शामिल कर रहे हैं. हालांकि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे अभी आधिकारिक रूप से एमवीए का हिस्सा नहीं है लेकिन उद्धव ने उसके साथ ही स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने का इरादा साफ कर दिया है. दोनों के बीच स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर काफी बात हो चुकी है. तभी यह सवाल है कि क्या महा विकास अघाड़ी मिल कर स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ेगा या मुंबई में शनिवार को जो एकजुटता दिखी वह सिर्फ वोट गड़बड़ी तक सीमित है?

एक और पवार की राजनीति में एंट्री

अजित पवार-सुप्रिया सुले से बेहद खास कनेक्शन

बारामती. महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर पवार परिवार की चर्चा है. वजह है बारामती में होने वाले नगर परिषद चुनाव. राज्य में स्थानीय चुनावों का ऐलान हो चुका है, और हर जगह चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं. अब बारामती में भी माहौल गर्म है क्योंकि यहां से अजित पवार के बेटे जय पवार के मैदान में उतरने की चर्चा जोरों पर है. उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे जय पवार अब सक्रिय राजनीति में कदम रखने की तैयारी में हैं.

माना जा रहा है कि वे बारामती नगर पालिका के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं. स्थानीय नेताओं के बीच यह चर्चा चल रही है कि जय पवार को महापौर पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है. पिछले साल हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जय पवार ने अपनी मां सुनेत्रा पवार और पिता अजित पवार के लिए प्रचार किया था. उन्होंने पूरे क्षेत्र में प्रचार अभियान चलाया था और वहीं से उनके राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई थीं.

पार्टी के अंदर भी बढ़ रही मांग- अब जब स्थानीय निकाय चुनाव करीब हैं, तो एनसीपी (अजित पवार गुट) के कई स्थानीय नेता भी जय पवार को चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि बारामती में युवा नेतृत्व की जरूरत है, और जय पवार इस भूमिका में फिट बैठते हैं.

अंदरखाने की खबर यह भी है कि अजित पवार खुद भी चाहते हैं कि उनके बेटे की राजनीतिक शुरुआत स्थानीय स्तर से हो, ताकि वे धीरे-धीरे अनुभव हासिल करें और जनता के बीच अपनी छवि बना सकें.

पार्थ पवार की गलती से सीख

पवार परिवार के राजनीतिक इतिहास को देखें तो इससे पहले पार्थ पवार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मावल सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था . उस समय कई लोगों ने कहा था कि पार्थ को जल्दबाजी में बड़ी राजनीति में उतार दिया गया . शायद इसी वजह से इस बार अजित पवार सावधानी बरत रहे हैं . वे नहीं चाहते कि जय के साथ वैसी गलती दोहराई जाए . इस बार रणनीति यह है कि जय की एंट्री स्थानीय चुनावों से हो, जैसे रोहित पवार ने की थी . रोहित ने जिला परिषद से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई .

विशेष | **चुनावी नतीजों में चौंकाने वाले आंकड़े**

मुस्लिम बहुल सीटों पर क्यों भारी पड़ता है एनडीए

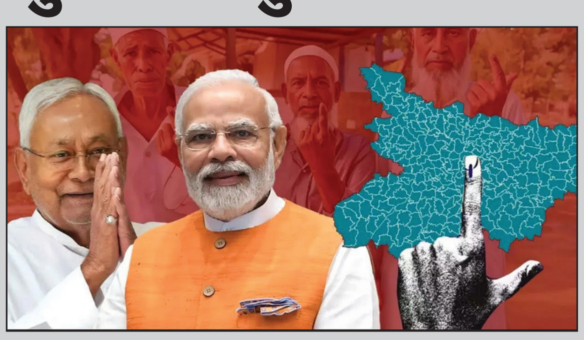

पटना. बिहार की चुनावी राजनीति में लगभग 18 प्रतिशत आबादी वाले मुस्लिम समुदाय का वोट हमेशा से चर्चा का विषय रहा है. राजनीतिक विश्लेषक इसे सत्ता की चाबी मानते हैं.

हालांकि, हाल के चुनावों के नतीजे बताते हैं कि मुस्लिम-प्रभावित क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा है. यह रुझान विशेष रूप से तब और मज़बूत हो जाता है जब भाजपा नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन में होती है, जिससे यह गठजोड़ लगभग अजेय हो जाता है.

चुनावी आंकड़े और एनडीए का स्ट्राइक रेट- राज्य में कुल 86 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी का प्रभाव निर्णायक माना जाता है. इनमें से 51 सीटों पर मुस्लिमों की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक है, जबकि 35 सीटों पर यह 18 प्रतिशत के आस-पास है. पिछले चुनाव में कांटे की टक्कर के बावजूद, एनडीए ने इन 86 महत्वपूर्ण सीटों में से 57 पर जीत दर्ज की. 20 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर तो राजग (एनडीए) का स्ट्राइक रेट 71 प्रतिशत रहा, जिसने एनडीए को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई. यहां तक कि 2010 की 'भाजपा लहर' में भी, एनडीए ने इन 86 सीटों में से 71 सीटें जीती थीं. उस समय 51 उच्च मुस्लिम-प्रभावित सीटों में से भाजपा को 27 सीटें मिली थीं और जदयू को 13 सीटों का लाभ हुआ था.

मतों का बिखराव और ध्रुवीकरण- मुस्लिम बहुल सीटों पर एनडीए की सफलता का प्रमुख कारण समानांतर ध्रुवीकरण और मुस्लिम मतों का बिखराव रहा है. विपक्षी महागठबंधन के पक्ष में मुस्लिम मतों के एकतरफा ध्रुवीकरण की आशंका के बावजूद, अल्पसंख्यक वोटों का एक समानांतर ध्रुवीकरण होता रहा है, जिसका सीधा लाभ सत्ताधारी एनडीए को मिला. सीमांचल (किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया) और पश्चिम चंपारण-मुंगेर जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 22 प्रतिशत से 68 प्रतिशत तक है, जो इन सीटों के नतीजों को प्रभावित करती है.

नीतीश का साथ भाजपा की बड़ी ताकत

इन सीटों पर भाजपा तब और भी अधिक मजबूत हो जाती है जब उसे नीतीश कुमार का साथ मिलता है. 2015 में जब नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़ दिया था, तब विपक्षी महागठबंधन को इन 86 सीटों में से अधिकांश (51 में से 34 और 35 में से 24) पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा केवल 22 सीटें ही जीत सकी थी. इस बार, राजनीतिक परिदृश्य में नए दावेदार भी उभरे हैं. अब बिहार की राजनीति में सक्रिय असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और जनसुराज पार्टी भी इस समुदाय पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं. एआइएमआइएम ने मुस्लिम-प्रभावित लगभग सभी सीटों पर इसी समुदाय के उम्मीदवार उतारने की रणनीति अपनाई है.